इंडियन इंस्टिटट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 5 अंक सं. : 12 जुलाई, 2013

संस्थान (इंस्टिटट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति की समीक्षा --1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां--2
बैंकिंग जगत की घटनाएं--- 2
विनियामकों के कथन ---3
इंटरनेट बैंकिंग और साइबर अपराध --4
बीमा /अर्थव्यवस्था---4
सूक्ष्मवित्त ---5
सहकारी बैंकिंग / विदेशी मुद्रा ---5
उत्पाद एवं गठजोड़---6
नयी नियुक्तियां /अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक------------------------------------ 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी / शब्दावली-------------------------------- 7
संस्थान की गतिविधियां ---7
संस्थान समाचार---7
बाज़ार की खबरें--8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति की मध्य-तिमाही समीक्षा - 17 जून 2013

मौद्रिक एवं चलनिधि सम्बन्धी उपाय

- अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 4.0% पर अपरिवर्तित रूप में कायम।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (Repo) दर 7.25% पर अपरिवर्तित।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत प्रति-पुनर्खरीद (Reverse Repo) दर 6.25% पर तथा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर एवं बैंक दर भी 8.25% पर अपरिवर्तित।

मुद्रास्फीति

मई माह के अनुमान के 4.7%, वर्ष 2012-13 में 7.4% के औसत स्तर से कम, रहने के परिणामस्वरूप सुर्खियों में आई थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति लगातार तीन माह कम रही। खाद्य को छोड़कर सभी घटक श्रेणियों में कमी आई है। ईंधन श्रेणी में बिजली की नियंत्रित कीमतों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन की आंशिक रूप से भरपाई करते हुए कोयले और खनिज तेल की कीमतों में कमी आई। खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में भी धातुओं की कीमतों, जिनमें वैश्विक कीमतों में कमी के प्रत्युत्तर में लगातार आठ माह तक गिरावट जारी रही, से बल पा कर ह्रास हुआ।

चलनिधि की स्थितियां

चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत निवल औसत दैनिक उधार राशियों में क्रमिक रूप से कमी आई, जो मार्च, 2013 के 1.2 ट्रिलियन रुपये से घट कर जून में (14 जून तक) 0.7 ट्रिलियन रह गई, जिससे जनवरी में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में कटौती, वर्ष 2012-13 की 4थी तिमाही के दौरान खुले बाज़ार के परिचालनों (OMOs) में खरीदियों, रिज़र्व बैंक के पास सरकार की नकद शेषराशियों में महत्वपूर्ण कमी तथा उसके साथ ही वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान अब तक 0.2 ट्रिलियन रुपये के खुले बाज़ार के दो परिचालनों के माध्यम से प्राथमिक चलनिधि के पर्याप्त निषेचन का पता चलता है।

बाहरी /विदेशी क्षेत्र

बाहरी/विदेशी क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना रही है विनिमय दर में उतार-चढ़ाव। वर्तमान वित्त वर्ष में 14 जून तक अमरीकी डालर के समक्ष रुपये में 5.8% का मूल्यह्रास हुआ। विदेशी संस्थागत

निवेशकों द्वारा औनी -पौनी बिक्री (sell-off) के कारण इसमें 22 मई -11 जून के दौरान 6.6% की गिरावट दर्ज हुई, जिससे अमरीकी फेड द्वारा मात्रात्मक कमी की संभाव्य निष्कासन (Tappering-off) की आशंकाओं द्वारा प्रवर्तित जोखिम विमुखता (Risk-off) के मानोभावों का निरूपण होता है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने सुलभ / सस्ती मुद्रा नीति के सम्बन्ध में चेतावनी जारी की

अंतरराष्ट्रीत निपटान बैंक (BIS) ने महत्वपूर्ण देशों में सुलभ मुद्रा नीतियों को लम्बे समय तक जारी रखे जाने के बारे में चेतावनी दी है, क्योंकि इससे आगे चल कर वित्तीय एवं मूल्यगत अस्थिरता पैदा हो सकती है। बैंकों के तुलनपत्रों पर चिंता व्यक्त करते हुए अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक ने बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए सदस्य बैंकों द्वारा बासेल-III मानदंडों के कार्यान्वयन पर बल दिया है, ताकि वे सरकारी सहायता पर निर्भर हुए बिना स्थिर लाभ अर्जित कर सकें। हाल के दिनों में कुछेक केन्द्रीय बैंक और अधिक सुलभता लाने से विरत हो गए हैं।

5 करोड़ रुपये से अधिक ऋण की आवधिक लेखा-परीक्षा

भरतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से जब तक कि ऋण की पूर्णत: चुकौती नहीं कर दी जाती, तब तक नियमित लेखा-परीक्षा के एक अंग के रूप में सम्बन्धित प्राधिकारियों से 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के ऋण जोखिमों से सम्बन्धित स्वत्वाधिकार विलेखों और अन्य प्रलेखों की आवधिक विधिक लेखा-परीक्षा तथा पुन: सत्यापन करवाने के लिए कहा है।

पूंजी निर्गमन के विवरण प्रकट करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को जारी किए गए सभी पूंजीगत लिखतों के विवरण उनके तुलनपत्रों में प्रकट करने का निदेश दिया है। बासेल -III बैंकिंग पूंजीगत सुधारों के अनुरूप जारी यह नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा तथा ऋणदाताओं को उनके सितम्बर के अंत वाले तुलनपत्रों में इसकी रिपोर्ट देनी होगी। आशा है कि इससे विनियामक पूंजी की पारदर्शिता बढ़ेगी तथा बाज़ार अनुशासन में सुधार होगा।

नये ऋण प्रावधान को बढ़ा कर 5% करें

बैंकों द्वारा ऋणों की पुनर्व्यवस्था पर शिकंजा कसते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नये मानक पुनर्व्यवस्थित अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण से सम्बन्धित आवश्यकता को 1 जून से पूर्ववर्ती 2.75% से बढ़ा कर 5% कर दिया है। पुनर्व्यवस्थित आस्तियों के मौजूदा स्टॉक के लिए प्रावधानीकरण तीन

वर्षों में चरणबद्ध रूपं में बढ़ा कर 5% कर दिया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के नये दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को पुनर्व्यवस्थित प्रत्येक 100 रुपये के लिए जून माह से 5 रुपये अलग रखने होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक की इस कार्रवाई से पुनर्व्यवस्थित खातों के अव्यवस्थित हो जाने पर बैंकिंग प्रणाली को अधिक उपधान प्राप्त हो सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को अनुपम ग्राहक पहचान कूट आबंटित करने हेतु और समय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ ऋणदाताओं द्वारा और समय की मांग किए जाने के बाद बैंकों को मौजूदा ग्राहकों को अनुपम ग्राहक पहचान कूट (UCIC) आबंटित करने हेतु और 10 महीनों का समय दिया है। आबंटन प्रक्रिया पूरी करने हेतु यह समय मई 2013 से बढ़ा कर 31 मार्च 2014 कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से सभी ग्राहकों को अनुपम ग्राहक पहचान कूट आबंटित करने के लिए कहा था, क्योंकि बढ़ती जटिलता और वित्तीय लेनदेनों के परिमाण यह आवश्यक बना देते हैं कि ग्राहक एक ही बैंक में बहुविध पहचान न रखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऋण से सोने के आयात पर रोक लगाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऋण के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा सोने के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है तथा इस मूल्यवान धातु की विदेशों से खरीद को नकद चुकाए और ले जाएं वाला व्यवसाय बना दिया है। इस कार्रवाई से खुदरा आभूषण व्यापार लगभग अपंग हो जाएगा और संभवत: इसके परिणामस्वरूप दो दशक पहले जब समाजवादी सरकारों ने सोने के आयात को प्रतिबंधित कर दिया था, की तुलना में देश में अपेक्षाकृत अधिक तश्करी होने लगेगी। स्वर्ण आयातकों द्वारा सोने के आयात के लिए बैंकों से साख पत्रों (LCs) के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। नामित बैंकों, एजेन्सियों द्वारा सभी श्रेणियों के अधीन सोने के आयात हेतु खोले जाने वाले सभी साख पत्र केवल 100% के नकद मार्जिन आधार पर ही होंगे। इसके अलावा, सोने के समस्त आयात आवश्यक रूप से भुगतान पर प्रदेय प्रलेख (DP) आधार पर ही होने चाहिए। स्वीकृति पर प्रदेय प्रलेख DA) आधार पर सोने के आयात की अनुमति नहीं होगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1.5, 2.5% की कूपन दर वाले 1,000 करोड़ रुपये के मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्ड बेचे

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में 1,000 करोड़ रुपये के ऐसे मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्ड (IIB) बेचे जिनमें खुदरा निवेशक अधिसूचित रकम के 20% तक की खरीद के लिए बोली लगा सकते थे। मूलधन और ब्याज दोनों का भुगतान थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के समक्ष समायोजित था तथा

जिनमें मूल्य-वृद्धि के समक्ष प्रतिरक्षण (Hedge) की व्यवस्था थी। मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्डों पर विशिष्ट रूप से बढ़ती मुद्रास्फीति वाले परिदृश्य में एक सुदृढ़ खरीद ब्याज मिलता है, क्योंकि निवेशक अपने प्रतिलाभ को संरक्षित करना चाहते हैं।

खुदरा अवसाद के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक उधार में गिरावट

आर्थिक मंदी के कारण छोटे शहरों और कस्बों में वाहनों और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कमजोर पड़ने के फलस्वरूप गैर-बैंकिंग कम्पनियों को बैंकों के उधार में गिरावट आ गई है। मार्च 2013 के अंत में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को दिए गए कुल ऋण 2.6 लाख करोड़ रुपये थे। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों से वार्षिक वृद्धि दर के एक वर्ष पहले के 25.3% से घट कर 14.7% के स्तर पर पहुंच जाने का पता चलता है। अप्रैल में उधार सपाट रहा। भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां मुख्यत: खुदरा ग्राहकों को वाहनों, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं एवं मकान खरीदने हेतु धनराशि उधार देती हैं। वे छोटे व्यवसायों तथा स्वनियोजितों को भी ट्रकों जैसे वाहनों की खरीद के वित्तीयन हेतु भी उधार देती हैं।

बैंक दबाव-परीक्षण के लिए पर्याप्त सुदृढ़

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) के अनुसार मुख्यत: वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक स्थितियों के कारण आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट के प्रति चिंताओं के बावजूद बैंकों की सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता बैंकिंग प्रणाली को दबावों का सामना करने में समर्थ बनाएगी। पैनल ने देश की बैंकिंग प्रणाली की आस्ति की गुणवत्ता तथा पूंजी पर्याप्तता की स्थिति का पुनरीक्षण किया। भारत की बैंकिंग प्रणाली की आस्ति की गुणवत्ता और पूंजी पर्याप्तता की स्थिति का पुनरीक्षण करने के अलावा परिषद ने वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC), जिसने अपनी रिपोर्ट मार्च में सरकार को सौंप दी है, की सिफारिशों को भी नोट किया।

संपर्क रहित भुगतान प्रौद्योगिकी

अब क्रेडिट या डेबिट कार्ड को स्वाइप करने या उन्हें बिक्री केन्द्र उपकरण में डालने जैसी किसी झंझट में नहीं पड़ना है। यह अजूबा कार्ड में अन्तर्निहित बेतार एन्टिना द्वारा संभव कर दिया गया है। वीसा के भारत एवं दक्षिण एशिया समूह के कन्ट्री मैनेजर श्री उत्तम नायक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब बैंकों द्वारा भारतीय बाज़ार के लिए इस संपर्क रहित भुगतान प्रौद्योगिकी विशेषता - वीसा पे वेव - पर विचार किया जा रहा है। अपेक्षाकृत त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने के अलावा इससे कार्डों की मलाई मारने (उनका दुरुपयोग किए जाने) या उनके साथ जालसाज़ी करने के जोखिम में भी कमी लाई जा सकेगी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा निर्यात राजस्व का एक वर्ष के भीतर प्रत्यावर्तन

देश में डालर के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) में स्थित इकाइयों से निर्यात से प्राप्त राशियों को निर्यात की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रत्यावर्तित करने के लिए कहा है। यह परिवर्तन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा एक वर्ष तक वैध होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह कार्रवाई ऐसे समय की गई है जब भारतीय रुपया डालर के समक्ष नये न्यून स्तर दर्ज करते हुए गहन दबाव की स्थिति से गुजर रहा है। इस उपाय के कारण अन्तर्वाह की सीमा के आगामी कुछ माह तक 5-6 बिलियन डालर रहने का अनुमान है, जिससे रुपये में तीव्र गिरावट रोकने में सहायता प्राप्त होगी।

वित्तीय समावेशन में दक्षिण आगे

वित्तीय समावेशन के नये सूचकांक पर आधारित भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (CRISIL) की एक रिपोर्ट से यह पता चला है कि दो में एक भारतीय के पास बचत बैंक खाता मौजूद है, किन्तु बैंक ऋण तक पहुंच सात में से केवल एक की ही है। पश्चिमी क्षेत्र (दक्षिण के बाद) 38.2 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसके बाद उत्तरी क्षेत्र (37.1), पूर्वी क्षेत्र (28.6) और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 28.5) के स्थान हैं। यद्यपि 40.1 के रूप में समग्र सूचकांक बहुत कम है, यह 2009 में 35.4 से बढ़ा है। उक्त रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि बचत खातों की संख्या (624 मिलियन) ऋण खातों (160 मिलियन) की लगभग चार गुनी है। 632 में से 618 जिलों ने वित्तीय समावेशन की दृष्टि से सुधार / वृद्धि की रिपोर्ट दी है। वित्तीय समावेशन की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर रहने वाले तीन राज्य हैं पुडुचेरी, चंडीगढ़ और केरल।

प्रमुख क्षेत्रों में ऋण वृद्धि धीमी पड़ी

भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्र-वार ऋण आंकड़ों से यह पता चलता है कि सभी प्रमुख क्षेत्रों को बैंक ऋणों (वैयक्तिक ऋणों को छोड़ कर) में पिछले वर्ष की अपेक्षा धीमी गति से वृद्धि का क्रम जारी है, जिससे अर्थव्यवस्था में मंदी की प्रवृत्ति जारी रहने का संकेत प्राप्त होता है। वैयक्तिक ऋणों में मई 2012 में 13% की तुलना में 16.3% की वृद्धि हुई। वैयक्तिक ऋणों वाले खण्ड में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं हेतु ऋणों में पिछले वर्ष के 13.5% की तुलना में 22% की वृद्धि हुई, जबकि आवास ऋण पिछले वर्ष के 10.2% की तुलना में 17.1% बढ़े। चूंकि ऋण की मांग धीमी पड़ गई, उनके द्वारा (बॉण्डों सहित) सभी स्रोतों से निधि संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में धीमा पड़ गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूलभूत सुविधा की परिधि में तीन और क्षेत्रों का समावेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मूलभूत सुविधा उधार की परिधि में तीन और क्षेत्र - यथा टेलीकॉम और दूरसंचार सेवाएं, घाढ़े द्रव पदार्थ वाली (Slurry) पाइपलाइनों और पूंजी निकर्षण को भी ला दिया है। इससे इन क्षेत्रों की कम्पनियों के लिए ऋण सस्ते हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप पांच वर्गीकृत श्रेणियों से 31 उप-क्षेत्र मूलभूत सुविधा क्षेत्र को उधार के पात्र हो गए हैं।

लिबोर वाले प्रकार के घोटाले की जांच के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पैनल का गठन

लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मान के भावी दुषरिणामों की पृष्ठभूमि में भारतीय रिज़र्व बैंक ने घरेलू बाज़ार में समतुल्य वित्तीय न्यूनतम मानदंडों पर पुनर्विचार करने हेतु एक समिति गठित की है। उक्त समिति मौजूदा न्यूनतम मानदंडों की प्रासंगिकता एवं उनके उपयोग का अध्ययन करेगी और सुधार अथवा नये मानदंडों के समावेश का सुझाव देगी। यह संगठनों के भीतर मानदंडों का परिकलन करते हुए अभिशासन की व्यवस्था पर भी विचार करेगी तथा इन संस्थाओं के सम्बन्ध में पर्यवेक्षी पर्यवेक्षण भी प्रस्तावित करेगी। उक्त समिति की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक श्री विजय भास्कर करेंगे तथा इसमें भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के प्रतिनिधियों, शिक्षाशास्त्रियों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों का समावेश होगा।

विनियामकों के कथन

ग्रामीण बैंकिंग आर्थिक क्रांति ला सकती है

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि "किसी ग्रामीण बैंक शाखा की शुरूआत से प्राय: उस गांव में एक आर्थिक क्रांति की शुरूआत होती है। आधार (UID), रू पे और किसान क्रेडिट कार्डो जैसी नयी प्रौद्योगिकीय पहलकदमियां आर्थिक क्रांति लाने में सहायक होंगी। ग्राहकों से इन सुविधाओं का उपयोग करने का अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि बैंकिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें धनराशि का आवर्तन होते रहना है और इससे यह गुणक प्रभाव उपलब्ध करा सकता है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक चालू खाते के उच्च घाटे पर ध्यान केन्द्रित करेगा

दरों में और कटौती की आशाओं को झुठलाते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि "मुद्रास्फीति के बढ़ने के जोखिमों की पृष्ठभूमि में चालू खाते के उच्च घाटे को रोकना उसकी प्राथमिकता होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा कि वृद्धि महत्वपूर्ण रूप से संयत हो गई है, मुद्रास्फीति कुछ हद तक अपने शिखर से घटी है, किन्तु भुगतान संतुलन दबावग्रस्त हैऔर निवेशों में तेजी आनी है। उन्होंने यह भी कहा कि "खुदरा मुद्रास्फीति अब भी अधिक है। लड़खड़ाती वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में कमी नहीं आ रही है। वैश्विक कीमतों, विशेषत: वस्तुओं की कीमतों में थोड़ी कमी आई होगी, किन्तु हम इसे इसी रूप में नहीं ले सकते।"

उच्च सरकारी शेषराशियों के परिणामस्वरूप चलनिधि में कठोरता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि सरकार की नकद शेषराशियों के उच्च स्तर के परिणामस्वरूप

चलनिधि की स्थिति कठिन हो रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान का कहना है कि "सरकार की शेषराशि पर्याप्त है तथा हम इस बात का आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं कि चलनिधि की कमी अस्थायी है या संरचनात्मक।" भारतीय रिज़र्व बैंक की दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) खिड़की से उधार ली गई राशियां 95,075 करोड़ रुपये थी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के +/- 1% के सहूलियत वाले स्तर से काफी अधिक थीं। इस वित्तीय वर्ष में अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक ने केवल एक खुले बाजार का परिचालन संचालित किया है- उसने 10,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित रकम के समक्ष 9,658 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां (G-secs) खरीदी हैं।

इंटरनेट बैंकिंग और साइबर अपराध

इंटरनेट बैंकिंग में वृद्धि के परिणामस्वरूप धोखाधड़िया केवल एक क्लिक की दूरी पर

भारत में कुल लेनदेनों में इंटरनेट बैंकिंग की हिस्सेदारी अब भी महत्वपूर्ण स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 13 में 69.4 लाख करोड़ रुपये के लेनदेनों के समक्ष विविध खुदरा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से 31.8 लाख करोड़ का निपटान किया गया था, जबकि 64 करोड़ रुपये के निपटान के समक्ष 18.6 लाख करोड़ रुपये का निपटान कार्ड से सम्बन्धित लेनदेनों के माध्यम से किया गया था। इसके अलावा,तत्काल सकल भुगतान प्रणाली अथवा आरटीजीएस के माध्यम किए गए 1,026 लाख करोड़ रुपये, जिसमें खुदरा एवं अंतर-बैंक, दोनों ही लेनदेन शामिल थे, के लेनदेन के समक्ष 6.85 करोड़ रुपये के लेनदेनों का निपटान किया गया था। युवा पीढ़ी बिलों का भुगतान करने और नकद अंतरण तथा चेकबुक प्राप्त करने से लेकर डेबिट कार्डों के लिए पासबुक प्राप्त करने जैसे बैंक से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए अधिकाधिक रूप से नेट लेनदेनों को अपना रही है। जहां बैंक ग्राहकों से नेट बैंकिंग अपनाने का अनुरोध कर रहे हैं, वहीं उनका विश्वास हासिल करने के लिए ग्राहकों को साइबर खतरों से बचाने का सामर्थ्य महत्वपूर्ण होगा।

मुख्य साइबर सुरक्षा खतरों की व्याख्या

मैलवेयर : दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का एक प्रकार, जिसमें अन्य चीजों के साथ-साथ वाइरसों, वोर्मों, स्पाईवेयर और छिपे शत्रुओं का समावेश होता है। जहां यह खतरे की कोई नयी संकल्पना नहीं है, वहीं कई बैंकों के पास अब भी जोखिम को नियंत्रणीय स्तर तक कम करने के पर्याप्त नियंत्रण नहीं हैं तथा नये प्रकार के मैलवेयर दैनिक आधार पर प्रवर्तित हो रहे हैं।

सामाजिक इंजीनियरिंग : से आशय है कर्मचारियों को गोपनीय सूचना प्रकट करने हेतु प्रभावित करके संगठन की सुरक्षा का उल्लंघन। इसमें मुख्य साधन होता है किसी कर्मचारी का विश्वास हासिल करने हेतु मनोवैज्ञानिक युक्तियों का उपयोग। यहां धोखाधड़ियों में एक कर्मचारी के रूप में

काम करते हुए पासवर्ड प्राप्त कर लेना अथवा नये कर्मचारियों की पहचान करने हेतु सामाजिक मीडिया का उपयोग करना और उन्हें ग्राहक के बारे में महत्वपूर्ण सुचना उपलब्ध कराने के लिए फंसा लेना।

फिशिंग : अनिवार्य रूप से ऐसे ई-मेल का प्रारूप तैयार करने से सम्बन्धित होती है जो प्राप्तकर्ताओं को नकली वेबसाइटें देखने के लिए आकर्षित करे। ये वेबसाइटें आम तौर पर व्यक्ति को वित्तीय और / अथवा वैयक्तिक सूचना उपलब्ध कराने हेतु सहमत कर लेने के लिए सुविख्यात और विश्वसनीय ब्रॉण्डों का उपयोग करते हुए तैयार की जाती हैं। इस प्रकार की जाली वेबसाइटें ऐसे दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम या कूट भेजती हैं जो संदेह न करने वाले प्रयोक्ता के कम्प्यूटर में संस्थापित हो जाते हैं तथा साइबर चोरों को भावी धोखाधड़ियों के लिए विवरण एकत्रित करने की सुविधा प्रदान करते हुए कार्डों के विवरण जैसी संवेदनशील सूचना संग्रहीत करते हैं।

सेवा प्रत्याख्यान (Dos) : सेवा प्रत्याख्यान हमला या वितरित सेवा प्रत्याख्यान हमला किसी मशीन या नेटवर्क संसाधन को उसके अभीष्ट प्रयोक्ताओं को अनुपलब्ध बना देने और सेवाओं को बाधित या निलंबित कर देने का प्रयास होता है।

अर्थव्यवस्था

वृद्धि की हिन्दू दर

हाल ही में जारी वर्ष 2012 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की 4.8% वृद्धि दर से दोहरे अंकों वाली वृद्धि का सपना पूर्णत: ध्वस्त हो गया है। इसने घटती अवधि अर्थात् वृद्धि की हिन्दू दर के लिए खिड़की भी खोल दी है। एक भारतीय अर्थशास्त्री प्रा. राजकृष्ण ने 1978 में धीमी वृद्धि को वर्णित करने तथा समाजवादी आर्थिक नीतियों की पृष्ठभूमि में इसे स्पष्ट करने के लिए "वृद्धि की हिन्दू दर" पद गढ़ा था। वृद्धि के कम होने और उसके लम्बी समायावधि तक जारी रहने के अलावा उक्त पद जनसंख्या वृद्धि को गुणित करते हुए प्रति व्यक्ति कम सकल घरेलू उत्पाद को भी समाविष्ट कर लेता है। 1980 वाले दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2% से अधिक थी और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर महज 1% थी। वर्तमान में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि प्रति व्यक्ति उच्चतर आय वृद्धि में सहायता करते हुए घट कर लगभग 1.4% हो गई है।

बीमा

उत्पाद अनुमोदन एक सप्ताह में

अब पुन: प्रवर्तन के लिए भेजे गए उत्पादों को 10 दिनों से कम समय में अनुमोदन प्राप्त हो सकता है। अब तक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने नयी विनियामक प्रणाली के तहत पारंपरिक उत्पादों के लिए 50 उत्पादों को मंजूरी दी है। इस वर्ष फरवरी में विनियामक ने पारंपरिक

उत्पाद दिशानिर्देशों में परिवर्तन अर्थात् अभ्यर्पण प्रभारों, उत्पाद के विन्यासों तथा एजेन्टों को प्रदत्त कमीशनों मे परिवर्तन की सूचनाा दी थी। इन मानदंडों के अनुसार ऐसे उत्पाद जो इन मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं, पुन: प्रवर्तित किए जाने होंगे। समूह बीमा उत्पादों को पुन: प्रवर्तित कराने की समय सीमा 1 जुलाई है और वैयक्तिक उत्पादों के लिए 1 अक्तूबर है।

न्यूनतम मृत्यु लाभ हेतु इर्डा की नयी श्रेणी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने गैर-सम्बद्ध उत्पाद विनियमनों के तहत न्यूनतम मृत्यु लाभ के भुगतान के लिए एक नयी श्रेणी की शुरूआत की है। अब 5 से 10 वर्षों तक की मीयाद वाले गैर-एकल प्रीमियम उत्पादों के लिए अन्य योजनाओं से अलग एक न्यूनतम मृत्यु लाभ उपलब्ध होगा। गैर-सहभागी उत्पादों के मामले में यह या तो मृत्यु की तिथि को भुगतान किए गए सभी प्रीमियमों के 105% वार्षिक प्रीमियम की पांच गुना या फिर परिपक्वता पर बीमाकृत /आश्वस्त सब से कम गारंटीकृत रकम या मृत्यु पर भुगतान किए जाने हेतु आश्वस्त कोई भी पूर्ण रकम, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, होगा। सहभागी उत्पादों के मामले में यह या तो वार्षिक प्रीमियम का पांच गुना या फिर मृत्यु पर भुगतान किए जाने हेतु आश्वस्त कोई भी पूर्ण रकम या परिपक्वता पर आश्वस्त सबसे कम गारंटीकृत रकम होगा।

सूक्ष्मवित्त

बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां इस वित्त वर्ष में 12% के मार्जिन पर उधार दे सकती हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसी बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी जो मुख्यत: एक सूक्ष्म वित्त संस्था (MFI) के रूप में परिचालन करती है, इस वित्त वर्ष में अपनी उधार लागत से 12% अधिक पर ऋण दे सकती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-सूक्ष्म वित्त संस्था को अपने अगस्त 2012 के निदेश में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्जिनों अर्थात् उधारकर्ताओं से लिये जाने वाले संस्था की उधार लेने की लागत से अधिक कीमत-लागत अंतर (Mark-up) को बड़ी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (100 करोड़ रुपये से अधिक ऋण पोर्टफोलियो) के मामले में 10% और अन्यों के मामले में 12% पर सीमित कर दिया था।

सिडबी ने सूक्ष्मवित्त प्लेटफार्म की शुरूआत की

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने देश में सूक्ष्मवित्त गतिविधियों के सम्बन्ध में "इंडिया माइक्रोफाइनैन्स प्लेटफार्म" नामक पोर्टल की शुरूआत की है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री सुशील मुहनोत का कहना है कि "यह पोर्टल सिडबी की उत्तरदायी वित्तीयन कार्यसूची की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सूक्ष्मवित्त क्षेत्र में और पारदर्शिता स्थापित करने में सहायक होगा। विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया यह प्लेटफार्म

जिला स्तर तक की प्रत्येक सूक्ष्मवित्त फर्म के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध कराएगा। यह भारतीय सूक्ष्मवित्त संस्थाओं के वार्षिक वित्तीय और परिचालनात्मक कार्य-निष्पादन के आंकड़े, बाज़ार के विकास एवं पोर्टफोलियो की गुणवत्ता से सम्बन्धित आंकड़े तिमाही आधार पर उपलब्ध कराएगा। सूक्ष्मवित्त क्षेत्र को अपने आपको जनता की अपेक्षाओं, विशेष रूप से निर्धारित आचार संहिता तथा उत्तर-पूर्व जैसे अल्प-सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त के प्रसार के अनुरूप ढालना पड़ता था।"

सहकारी बैंकिंग

सोने के सिक्कों पर ऋण के बारे में सहकारी बैंकों पर रोक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोने के समक्ष अग्रिम पर प्रतिबंध को सहकारी बैंकों पर भी लागू कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बैंकों द्वारा बेचे जाने वाले विशेष रूप से ढाले गए सोने के सिक्कों की प्रतिभूति के समक्ष अग्रिम मंजूर करते समय राज्य/मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिक्के/ सिक्कों का वजन प्रति ग्राहक 50 ग्राम से अधिक न हो।

विदेशी मुद्रा

जुलाई, 2013 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.68565	0.495	0.784	1.177	1.510
जीबीपी	0.89750	0.8050.	0.9957	1.2690	1.5261
यूरो	0.46929	0.601	0.782	0. 998	1.220
जापानी येन	0.42071	0.281	0.343	0.415	0.510
कनाडाई डालर	1.50000	1.557	1.777	2.017	2.228
आस्ट्रेलियाई डालर	2.64740	2.815	3.075	3.3 68	3.585
स्विस फ्रैंक	0.24640	0.230	0.403	0.600	0.793
डैनिश क्रोन	0.64170	0.8140	1.0070	1.2335	1.4475
न्यूजीलैंड डालर	2.86250	3.210	3.503	3.735	3.925
स्वीडिश क्रोन	1.31700	1.520	1.752	1.997	2.183
सिंगापुर डालर	0.50500	0.640	0.985	1.355	1.690
हांगकांग डालर	0.50000	0.680	0.960	1.320	1.650
एमवाईआर	3.26000	3.320	3.390	3.490	3.650

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	21 जून, 2013 के दिन	21 जून, 2013 के दिन
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	17, 018, 4	2 87,845 7
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	15, 338.1	2 58,432. 7
ख) सोना	1, 290, 0	22, 836. 0
ग) विशेष आहरण अधिकार	259, 5	4, 372.6
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	130.8	2, 204.4

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

कमजोर रुपये के कारण भारतीय बैंकों में अनिवासी भारतीय जमा प्रवाहों में मज़बूती

अनिवासी भारतीयों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी डालर निधियां रुपये में मूल्य की दृष्टि से अधिक प्रतिफल दें मुद्रा में गिरावट का निरंतर रूप से फायदा उठाया है। इसके परिणामस्वरूप ऐसे समय में जब रुपया कमजोर है जमाराशियों का सुदृढ़ अंतर्वाह हुआ है। पिछले दो वित्तीय वर्षों में जब रुपये का मूल्य गिर गया था, अनिवासी भारतीय जमाराशियों में वित्त वर्ष 12 और 13 में क्रमश: 21.2% और 12.2% की वृद्धि हुई। पिछले वित्त वर्ष में दिसम्बर 2011 में घोषित अनिवासी (विदेशी) रुपया (NRE) और अनिवासी साधारण (NRO) खातों में ब्याज दरों के आंशिक रूप से अविनियमन के कारण अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि देखने में आई थी। अविनियमन के बाद घरेलू बैंक इन खातों पर 9% - 10% तक की उच्च्च दरे प्रदान कर रहे थे और इससे अनिवासी जमाराशियों के अप्रैल, 2012 के अंत में 59 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अप्रैल 2013 में 72 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने में सहायता प्राप्त हुई। अनिवासी खातों में निधियां, जो दिसम्बर, 2011 में 25.5 बिलियन अमरीकी डालर थीं, अब 47 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गई हैं।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य

भारतीय स्टेट बैंक	स्पैनिश बैंक बैंको बिलबाओ विजकाया अर्जेन्टीना, एसए (बीबीवीए)	लातीनी अमेरिका और स्पेन में कारबार का विकास करने।
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी)	15 वर्ष की डोर-टू-डोर अवधि के लिए 490 करोड़ रुपये के एक ऋण के लिए और इसका उपयोग कम्पनी के पूंजीगत व्यय का आंशिक वित्तीयन करने में किया जाएगा।
इलाहाबाद बैंक	भारतीय जीवन बीमा निगम	सूक्ष्म-बीमा उत्पाद बेचने के लिए।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
श्री के.आर. कामत	अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (IBA)
श्री टी.एम. भसीन	उपाध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (IBA)
श्री एस.के. राय	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश:)

दबाव-परीक्षण पर चर्चा जारी रखते हुए इस अंक में हम सिद्धांत 8 पर विचार करते हैं जो उन विविध परिदृश्यों को रेखांकित करता है जिनका जोखिम प्रबंधक को वह जिस जोखिम का वह सामना कर रहा है उसके एन आयामों को प्राप्त करने हेतु उपयोग करना चाहिए।

8. दबाव-रीक्षण कार्यक्रमों में अग्रगामी समजे जाने वाले परिदृश्यों सहित विविध परिदृश्यों का समावेश होना चाहिए तथा उनका लक्ष्य प्रणाली-व्यापक अन्योन्य क्रियाओं एवं प्रति-सूचना के प्रभावों को ध्यान में रखना होना चाहिए।

किसी प्रभावी दबाव-परीक्षण कार्यक्रम में घटनाओं के वर्णक्रम और गहनता के स्तरों के साथ परिदृश्य शामिल होने चाहिए। ऐसा करने से सुभेद्यताओं और अरैखिक हानि प्रोफाइलों के प्रभाव के प्रति प्रबन्धन की समझ को गहन बनाने में सहायता प्राप्त होगी। प्रच्छन्न सुभेद्यताओं की पहचान करने के लिए दबाव-परीक्षण लचीली एवं काल्पनिक विधि से किया जाने चाहिए। कल्पना की विफलता के परिणामस्वरूप चरम घटनाओं की संभावना और गहनता का न्यून अनुमान लगाया जा सकता है तथा बैंक के लचीलेपन के बारे में सुरक्षा की एक गलत भावना पैदा हो सकती है।

दबाव-परीक्षण कार्यक्रम में पोर्टफोलियो के विन्यास में परिवर्तनों, नयी सूचना तथा जोखिम की ऐसी उभरती संभावनाओं जिनका समावेश पारंपरिक जोखिम प्रबन्धन पर निर्भर रहते हुए अथवा पूर्ववर्ती

जोखिम घटनाओं की अनुकृति के माध्यम से नहीं हो पाया था उन्हें शामिल करने के लिए भविष्योन्मुखी परिदृश्यों को शामिल किया जाना चाहिए। भविष्योन्मुखी परिदृश्यों के संकलन के लिए पूरे संगठन में विशेषज्ञों के ज्ञान और निर्णय के संयोजन की आवश्यकता होती है। ये परिदृश्य वरिष्ठ प्रबन्धन के वार्तालाप एवं निर्णयों पर आधारित होने चाहिए। चर्चा को प्रोत्साहित करना तथा बैंक के विभिन्न स्तरों पर मौजूद सूचना का लाभप्रद रीति से उपयोग करना एक चुनौती है।

किसी उपयुक्त दबाव-परीक्षण ढांचे में फर्म-व्यापी दबाव-परीक्षणों और उसके साथ ही उत्पाद, व्यवसाय और कम्पनी/संस्था विशिष्ट दबाव-परीक्षणों सहित दानेदारी की विभिन्न स्तरों वाले जोखिमों के समावेश वाले व्यापक श्रेणी के परिदृश्य शामिल होने चाहिए। कुछेक दबाव परिदृश्यों को बैंक की वित्तीय शक्ति पर गंभीर दबाव वाली घटनाओं के फर्म-व्यापी प्रभाव के प्रति अन्तर्दृष्टि प्रदान करनी चाहिए तथा इन घटनाओं पर अनुक्रिया व्यक्त करने के बैंक के सामर्थ्य का मूल्यांकन करने में समर्थ बनाना चाहिए। सामान्य रूप से दबाव परिदृश्यों को विशिष्ट व्यवसाय क्षेत्रों की सारता और आर्थिक एवं वित्तीय स्थितियों में परिवर्तनों के प्रति उनकी सुभेद्यता का निरूपण करना चाहिए।

वित्तीय संकट ने यह दिखा दिया है कि दबाव की घटनाओं की संभाव्यताओं का सही अनुमान लगाना समस्यापूर्ण कार्य है। संभाव्यता का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाले सांख्यिकीय सम्बन्ध दबावग्रस्त स्थितियों में विफल हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में संकट ने सम्बन्धित परिदृश्यों को भविष्योन्मुखी परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने में विशेषज्ञ निर्णय को उपयुक्त अधिमान दिए जाने के महत्व को रेखांकित किया है।

दबाव परीक्षण में विश्लेषित अनाश्रयताओं की जोखिम विशिष्टताओं के आधार पर विविध समय संस्तरों तथा इस बात का समावेश होना चाहिए कि किसी विशिष्ट परीक्षण का आशय युक्तिपूर्ण या रणनीतिक उपयोग है या नहीं। जोखिम प्रबन्धन के उद्देश्य से किए जाने वाले दबाव-परीक्षणों का स्वाभाविक प्रारंभ बिन्दु लक्ष्यांकित पोर्टफोलियो का प्रासंगिक जोखिम प्रबन्धन संस्तर और अन्तर्निहित अनाश्रयताओं की चलनिधि होती है। हालांकि, इसकी तुलना में पर्याप्त रूप से व्यापक अवधियों का समावेश किए जाने की जरूरत है, क्योंकि चलनिधि की स्थितियां दबाव वाली स्थितियों में द्रुत गति से बदल सकती हैं। बैंक को मध्यम से दीर्घ समय संस्तर में अनुक्रिया व्यक्त करने के उसके सामर्थ्य सहित मंदी वाले प्रकार के परिदृश्यों का भी मूल्यांकन करना चाहिए। बैंक को मान्यताओं के बढ़े हुए महत्व को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि किसी दबाव-परीक्षण का समय संस्तर लम्बा हो जाता है। बैंक को इस प्रकार के दबाव-परीक्षणों में प्रति-सूचना के प्रभावों और फर्म विशिष्ट तथा बाज़ार-व्यापी अनुक्रियाओं को भी शामिल करने पर विचार करना चाहिए।

स्थूल-आर्थिक एवं वित्तीय आघातों के समुच्चय के संभाव्य प्रभावों का विश्लेषण करते समय बैंक का लक्ष्य प्रणाली-व्यापक संवादों तथा प्रति-सूचना के प्रभावों को भी ध्यान में रखना होना चाहिए। हाल की घटनाओं ने यह दिखा दिया है कि इन प्रभावों में इक्का-दुक्का दबाव वाली घटनाओं को बड़े और अच्छी तरह पूंजीकृत बैंकों तथा उनके साथ ही प्रणालीगत स्थिरता को भी खतरे में डालने वाले वैश्विक संकट में रूपांतरित कर देने की क्षमता होती है। चूंकि ये बहुत कम घटित होती हैं, वे सामान्यतया दैनिक जोखिम प्रबन्धन में प्रयुक्त पारंपरिक डाटा श्रृंखलाओं में नहीं रोकी जातीं। विशेषज्ञ निर्णय से समर्थित दबाव-परीक्षण इन कमियों का एक सक्रिय प्रक्रिया में निराकरण करने में सहायक हो सकता है तथा उससे जोखिम की पहचान करने में सुधार हो सकता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

परिपक्वता पर प्रतिफल (YTM)

प्रतिफल शब्द अनिवार्य रूप से किसी प्रतिभूति पर लाभ से सम्बन्धित है। किसी बॉण्ड पर प्रतिलाभ को भी उसका प्रतिफल कहा जाता है। परिपक्वता पर प्रतिफल (YTM) बॉण्ड की आंतरिक प्रतिलाभ दर (IRR) होती है। किसी परियोजना की आंतरिक प्रतिलाभ दर वह बट्टा दर होती है जो जो भावी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य को प्रारंभिक निवेश के बराबर ला देती है। पूंजी बजट-निर्माण की शब्दावली में यह वह बट्टा दर होती है जो निवल वर्तमान मूल्य (NPV) को शून्य के बराबर लाती है। किसी बॉण्ड धारक को आय तीन स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला, उसे आवधिक ब्याज या कूपन भुगतान मिलता है। दूसरा, वह अपने आप में ब्याज का निरूपण करने वाले इन कूपनों को पुनर्निविष्ट करके ब्याज अर्जित कर सकता है (इसे ब्याज पर ब्याज के रूप में देखा जा सकता है)। अंत में परिपक्वता के समय वह अंकित मूल्य के अनुसार आय अर्जित करेगा। किसी कागजी प्रतिफल की गणना को आय के इन तीनों ही स्रोतों में मौजूद होना चाहिए।

शब्दावली

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) एक ऐसी दर होती है जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCBs) अपनी सम्बन्धित निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के एक प्रतिशत तक एक दिवसीय उधार ले सकते हैं। इस सुविधा से ली गई रकम पर ब्याज दर पुनर्खरीद (Repo) दर से 100 आधार अंक अधिक होगी। इस सुविधा से एक दिवसीय अंतर-बैंक बाज़ार में अस्थिरता को रोकने की आशा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीमांत स्थायी सुविधा की शुरूआत की घोषणा 3 मई, 2011 को की और यह 9 मई, 2011 से प्रभावी हुई।

संस्थान की गतिविधियां

जुलाई, 2013 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	आवास वित्त पर 3रा कार्यक्रम	8 से 10 जुलाई, 2013 तक
2	ऋण मूल्यांकन (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अग्रिम) पर 6ठा कार्यक्रम	22 से 26 जुलाई, 2013 तक
3	अपने ग्राहक को जानिए / ऋण शोधन निवारण / आतंकवाद का मुकाबला पर 3रा कार्यक्रम	22 से 24 जुलाई, 2013 तक

4	खुदरा बैंकिंग पर 2रा कार्यक्रम	29 जुलाई से 2 अगस्त 2013 तक

जून, 2013 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	विपणन एवं ग्राहक सेवा पर 3रा कार्यक्रम	3 से 7 जून, 2013 तक
2	व्यापार वित्त पर 2रा कार्यक्रम	10 से 14 जून, 2013 तक
3	टॉपसिम तुलनपत्र अनुरूपण	17 से 18 जून, 2013 तक
4	8वां लीडरशिप कार्यक्रम - पीडीआई 9वां हाउस	17 से 19 जून, 2013 तक

संस्थान समाचार

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (ICSI) और इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स के बीच 16 जून, 2913 को कारपोरेट अभिशासन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (ICSI), नवी मंबई में एक समझौता ज्ञापन हस्तारित किया गया है। उक्त समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (ICSI) के सदस्यों और बैंकों में कार्यरत सीएआईआईबी उत्तीर्ण अधिकारियों के लिए 'बैंकिंग कम्प्लाएंस प्रोफेशनल' नामक एक प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है।

"ग्राहक सेवा और बैंकिंग संहिता एवं मानक" पर संगोष्ठी

संस्थान ने 21 जून, 2013 को बेंगलूरू में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) के सहयोग से "ग्राहक सेवा और बैंकिंग संहिता एवं मानक " पर 9वीं संगोष्ठी का आयोजन किया था। मुख्य व्याख्यान केनरा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.के. दुबे द्वारा दिया गया और समापन व्याख्यान श्री एम. पलानीसामी, बैंकिंग लोकपाल, कर्नाटक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया। उक्त संगोष्ठी में 121 सहभागियों ने भाग लिया।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

ई-मेल के माध्यम से आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने आईआईबीएफ - विज़न उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करा रखे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते यथाशीघ्र पंजीकृत करा लें। आईआईबीएफ - विज़न संस्थान के पोर्टल में डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

नये पाठ्यक्रमों की शुरूआत

संस्थान ने 12 जुलाई, 2013 को 2 नये पाठ्यक्रमों यथा- सर्टिफाइड बैंकिंग कम्प्लाएंस प्रोफेशनल और सर्टीफाइड बैंक ट्रेनर की शुरूआत की है। अधिक विवरण के लिए संस्थान की वेबसाइट देखें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
* प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रेषित
* प्रेषण की तिथि प्रत्येक महीने की 25वीं से 30वीं तारीख

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

100.00
90
85
80
75
70
65
60
55
50
03/06/13 05/06/13 06/06/13 10/06/13 11/06/13 12/06/13 14/06/13 18/06/13 20/06/13 21/06/13 26/06/13 27/06/13 28/06/13

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- लगातार पांचवे सत्र में अपनी गिरावट की प्रवृत्ति को जारी रकते हुए 3री को रुपये में 26 पैसे की गिरावट दर्ज हुई जिससे अंतिम क्षण पर डालर की खरीद और स्थानीय इक्विटियों से पूंजी बहिर्वाह के कारण वह 56.76 के 11 माह के नये न्यून स्तर पर पहुंच गया।
- 4थी के 56.44/45 की तुलना में 5वीं को रुपया प्रति डालर 56.7250 / 7350 पर बंद हुआ। 5 वीं को विशेष रूप से तेल तेल क्षेत्र के आयातकों,से डालर की भारी खरीद तथा यूरो में कमजोरी से प्रभावित हो कर रुपये में एक सप्ताह में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई।
- सोमवार, 10वीं को भारतीय रुपया डालर के समक्ष 58.15 के रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ - जो 110 पैसे की गिरावट थी - और वह अमरीकी अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान के सुदृढ़ संकेतों, जो वैश्विक निवेशकों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं से धनराशि आहरित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, के बीच प्रति डालर 60 के स्तर को पार कर जाने की राह पर अग्रसर लगा।
- 20वीं को अमरीकी फेडरल रिज़र्व द्वारा अपने मौद्रिक प्रोत्साहन कार्यक्रम को 2014 के मध्य तक समाप्त कर देने की समय-सीमा का संकेत दिए जाने के बाद डालर के समक्ष रुपया 59.99 के रिकार्ड न्यून स्तर पर आ गया और प्रति डालर 59.57 पर बंद हुआ।
- 26वीं को डालर के समक्ष रुपया 20 जून को दर्ज 59.98 के रिकार्ड निचले स्तर को पार करते हुए गिर कर 60.76 पर पहुंच गया। व्यापारियों ने इस गिरावट के लिए घरेलू आयातकों से माह के अंत वाली मांग तथा अधिकांश उभरती एशियाई मुद्राओं में गिरावट को जिम्मेदार ठहराया।

भारित औसत मांग दरें

7.4
7.3
7.2
7.1
7
6.9
6.8

01/06/13 04/06/13   07/06/13 08/06/13   12/06/13 14/06/13 15/06/13 18/06/13 21/06/13
22/06/13 24/06/13 25/06/13 28/06/13

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- उधार लेने वाले बैंकों से मांग के अभाव में 4थी को मांग दरें कमतर स्तर पर बंद हुईं। दर 7.35 और 7.15 प्रतिशत की श्रेणी में घटते-बढ़ते हुए 7.25% के न्यून स्तर पर बंद हुईं।
- 5वीं को उधार लेने वाले बैंकों से नयी मांग पर एक दिवसीय मुद्रा बाजार में मांग दरों में पुनरुत्थान हुआ। यह दर 7.25% के बंद वाले स्तर से उच्चतर स्तर 7.30% पर बंद हुई।
- सामान्यतया दरें 6.9 और 7.3 के बीच श्रेणीबद्ध रहीं।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

19800
19600
19400
19200
19000
18800
18600
18400

03/06/13 05/06/13 10/06/13 13/06/13 14/06/13 17/06/13 20/06/13 24/06/13 25/06/13 26/06/13 27/06/13 28/06/13

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जुलाई, 2013